मुम्बई के विकास के लिये निधियां

4285. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के विकास के लिये 1000 करोड़ रुपये की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) सरकार मुम्बई के विकास के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार रखती है और इसे कब से स्वीकृत किया जाने वाला है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं । राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों की नगर विकास योजनाओं के लिए निधियों का नियतन संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्तावों के आधार पर संघ योजना आयोग द्वारा किया जाता है । कतिपय विशेष केन्द्रीय योजनाओं, जिनके लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बजट में प्रावधान किया जाता है, के अलावा समस्त आबंटन राज्य क्षेत्र में किए जाते हैं ।

बम्बई में आवास तथा मलिन बस्तियों का सामना करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को विशेष अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । इसके अतिरिक्त, नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बम्बई में मलिन बस्ती उन्मूलन, मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र सरकार को इस शर्त पर एक ही बार 50 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा भी इस प्रयोजनार्थ इतनी ही राशि का सदृश प्रावधान किया जाएगा ।

इन अनुदानों के अतिरिक्त, 1115.71 करोड़ रुपये की कुल लागत से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त बम्बई नगर विकास परियोजनाएं तथा बम्बई जल आपूर्ति तथा मल निर्यात परियोजना कार्यान्वयनाधीन हैं । इनमें मलिन बस्ती उन्नयन, स्थल सेवा, जलापूर्त्ति तथा मलनिर्यास, बरसाती पानी की निकासी, सड़कें, ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा प्रशिक्षण और उपकरण हेतु तकनीकी सहायता परियोजनाएं शामिल हैं ।

Clearance of backlog of houses

4286. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the backlog of housing at the end of Sixth and Seventh Five Year Plans;

(b) the estimated backlog thereof by the turn of the century;

(c) the steps taken by Government to ease the problem of housing; and

(d) the specific steps taken to make available critical inputs to the lower and middle class people as well as weaker sections of the population?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Based on the 1981 census figures, the backlog of housing has been estimated to be 26 million by the end of the 6th Plan, 30.3 million by the end of 7th Plan and 41 million by the turn of the century.

(c) and (d) Housing being a State subject, it is the responsibility of the State Governments and Union Territory Administrations to formulate housing schemes for various target groups from their State plans. The draft National Housing Policy envisages specific measures for increasing the access of the poor and disadvantaged sections to various housing inputs. However, considering the importance of this sector Central Government also provides financial assistance to the States as well as Union Territory agencies through financial institutions like National Housing Bank, HUDCO etc., for housing activities. Indira Awas Yojana is a centrall